Ministry of Environment and Forests has, inter-alia, recommended encouraging the development and use of returnable plastic trays, card board boxes, corrugated fibre board boxes, multiwalled craft paper racks and polythene laminated jute boxes for packing, replacement of wooden sleepers by concrete sleepers, encouraging panels manufactured out of non-wood material like bagasse, rice husk, jute, etc., shifting from the use of timber to steel in construction and furniture, and exemption in excise duty on plastic, steel and aluminium furniture.

पूंजी निवेश

*238. **श्री सोमपाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप, किन किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश किया गया है और इसका किन किन राज्यों को लाभ मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त पूंजी निवेश का लाभ पिछड़े राज्यों तक नहीं पहुंच पाया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में अधिक अधिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) लाइसेंस-मुक्त उद्योगों के लिये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन मुख्यत: धातुकर्मी, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, वस्त्र और विद्युत मशीनरी क्षेत्रों के लिये प्रस्तुत किये गये हैं। लाइसेंस प्राप्त उद्योगों के लिये आशय-पत्र मुख्यत: औषधि और भेषज, फर्मेंटेशन उद्योग, रसायन उद्योग आदि के लिये मंजूर किये गये हैं। निवेश करने की इच्छा रखने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 38 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक उद्यम ज्ञापन और 48 प्रतिशत से अधिक आशय-पत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिये दिये गये हैं।

1993-94 के बजट में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सिक्किम, गोवा और संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षदीप और पांडिचेरी में नये औद्योगिक उपक्रमों के लिये पांच वर्ष के करावकाश का प्रस्ताव है जो उत्पादन के वर्ष से शुरू होगा।

Additional outlay for the minimum needs programme

*239. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an additional outlay of Rs. 500 crores has been made in the Eighth Plan for a new component of the Minimum Needs Programme for Rural Domestic Energy incorporated into the Integrated Rural Energy Programme (IREP); and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) A provision of Rs. 500.00 crores has been made in the Eighth Plan for the Minimum Domestic Energy Needs of the economically weaker sections in the blocks covered under the Integrated Rural Energy Programme. The Programme details and its funding arrangements are benig worked out.

जवाहर रोजगार योजना के अधीन राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

*240. **श्री मूल चन्द मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अधीन, केन्द्रीय सरकार से राजस्थान